>

Title : Reported incident of virginity test conducted on the brides in community marriage ceremony under the Mukhya Mantri Kanya Yojana in Shaldol district, Madhya Pradesh.

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कन्यादान योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रशासन द्वारा अमानवीय, अमर्यादित, अनैतिक और कानूनी कृत्य, जिसमें विवाह पूर्व मैडिकल परीक्षण के दौरान महिलाओं की अस्मिता और सम्मान पर जो चोट पहुंचायी गयी है, के विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, इस मामले में पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी विधान सभा में दे चुके हैं। ...(व्यवधान) यह गलत जानकारी है और सदन को गुमराह करने की कोशिश है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉ. व्यास जी, आप अपनी बात कहें।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, सदन को बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान)

मुझे सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार निश्चित तौर पर सरकार ने माना है कि मैडिकल परीक्षण हुआ है। इसका कारण बताया गया है कि पूर्व में कराये गये विवाह के दौरान एक प्रसव हो गया था। जो महिला प्रेगनेंट है, उसे किस कारण से, किस नैतिकता के आधार पर, किस कानून के आधार पर विवाह से रोका जा सकता है। इसका उत्तर दिया गया कि भारतीय वैवाहिक पद्धति के अनुसार उसका विवाह नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण, अप्रासांगिक तथा अनैतिक व्यवहार किया गया है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है।

महोदय, मैं मांग करती हूं कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और दोषी व्यक्तियों को दंड दे। किसी भी योजना का अंत अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि उसका साधन अनुपयुक्त है तो यह ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसने जो योजना बनायी है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है।

महोदय, इसे पब्लिकली महिलाओं का मैडिकल परीक्षण कहें या इसे कौमार्य परीक्षण कहें, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहती हूं।

लेकिन सरकार ने माना है कि परीक्षण हुआ है और पब्लिकली परीक्षण इस बात का द्योतक है कि महिलाओं की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया है, उनकी प्राइवेसी पर चोट हुई है, उनकी अस्मिता पर चोट हुई है। इसलिए केन्द्र सरकार समस्त राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि योजना बनाते हुए और योजना के क्रियान्वयन के समय महिलाओं की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाए। केन्द्र सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को आगाह करे और यह सुनिश्चित करे कि इस योजना को पूरी तरह से देखकर ही उसका आगे क्रियान्वयन हो।